गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 271
दि. 02.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

राहत नहीं, रफ्तार का बजट

बजट 2026-27 में लोकलुभावन वादों से दूरी, विकास की लंबी लकीर

जीएनएस)। नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया केंद्रीय बजट साफ संकेत देता है कि सरकार ने इस बार तात्कालिक राहत या लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय देश की आर्थिक दिशा और भविष्य की मजबूती पर फोकस किया है। 53.47 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय वाले इस बजट को "रोडमैप बजट" कहा जा सकता है, जिसमें विकास, निवेश, रोजगार और स्थिरता को केंद्र में रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 85 मिनट के भाषण में यह स्पष्ट किया कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात के बीच भारत को दीर्घकालिक मजबूती देना प्राथमिकता है। इस बजट का आकार पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 49.64 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 7.7 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद आम आदमी के लिए बड़े लोकलुभावन ऐलान नहीं किए गए। सरकार का तर्क है कि स्थायी विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, कृषि सुधार और वित्तीय अनुशासन जरूरी है। इसी सोच के तहत बजट में पूंजीगत व्यय, उद्योग, छोटे कारोबार, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खास जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। कुल बजट का करीब 32 प्रतिशत हिस्सा बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। सड़कों, रेलवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर, बंदरगाहों और शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान किया गया है। रेलवे के लिए लगभग 2.93 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय तय किया गया है, जिससे नई लाइनों, दोहरीकरण और सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार पैदा होंगे और निजी निवेश को भी गति मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इसमें आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नौसेना व वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। रक्षा पेंशन पर भी बड़ा खर्च रखा गया है, जो सैनिकों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी बजट में स्पष्ट रणनीति दिखती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिला है। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य पालन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की घोषणा से जल प्रबंधन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही किसानों के लिए भारत-VISTAAR जैसे एआई आधारित टूल शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिससे खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। छोटे उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को बजट में खास तवज्जो दी गई है। 200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना, 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत निधि में अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई को रोजगार सृजन और निर्यात का मजबूत इंजन बनाया जाए। इसके लिए वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच आसान करने के उपाय किए गए हैं। शिक्षा, कौशल और रोजगार के मोर्चे पर भी बजट भविष्य की तैयारी करता दिखता है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास विश्वविद्यालय टाउनशिप, हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, नए आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटैलिटी संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। पर्यटन क्षेत्र में 20 प्रमुख स्थलों पर गाइड्स के कौशल विकास की योजना से रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए बजट में कई अहम पहलें की गई हैं। महिला उद्यमियों के लिए SHE Marts, विशेष स्किल प्रोग्राम और लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी तो समग्र विकास को रफ्तार मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन इस बजट की एक और बड़ी विशेषता है। सरकार ने 2026-27 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। कर्ज-जीडीपी अनुपात को भी धीरे-धीरे घटाने की योजना है, ताकि ब्याज भुगतान का बोझ कम हो और विकास कार्यों के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध हों। ब्याज भुगतान पर बजट का लगभग 20 प्रतिशत खर्च होने के बावजूद सरकार का फोकस कर्ज नियंत्रण पर बना हुआ है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 राहत से ज्यादा दिशा दिखाने वाला दस्तावेज है। इसमें आम आदमी के लिए तात्कालिक फायदे कम जरूर हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, शिक्षा और वित्तीय स्थिरता पर जो जोर दिया गया है, वह आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने की कोशिश है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि यह बजट चुनावी नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का बजट है।

बजट का कुल खाका

वित्त मंत्री ने बताया कि 2026-27 में कुल खर्च 53,47,315 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। पिछला बजट प्रावधान 50,65,345 करोड़ रुपये का था, जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 49,64,842 करोड़ रुपये किया गया था। नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 32 प्रतिशत खर्च प्रस्तावित है, जबकि ब्याज भुगतान पर लगभग 20 प्रतिशत राशि जाएगी। सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी

इस बार रक्षा क्षेत्र को 7,84,678 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इसमें से 1,71,338 करोड़ रुपये पेंशन मद में खर्च होंगे। नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये और विमान व एयरो इंजन निर्माण के लिए 63,733 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का जोर स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आधुनिकीकरण पर साफ नजर आया।

रेलवे और परिवहन पर फोकस

रेलवे को 2,93,030 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। नई लाइनें, दोहरीकरण और लॉजिस्टिक सुधारों पर खास ध्यान रहेगा। इसके साथ ही देश में सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जो परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत देती है। कुल परिवहन मद में 5,98,520 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव है।

खेल बजट को नई ऊंचाई

युवा मामले और खेल मंत्रालय का बजट पहली बार 5,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। 2026-27 में इसे 4,479.88 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले साल से 1,133.34 करोड़ रुपये अधिक है। इससे खेल ढांचे, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय तैयारियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट मिला है। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन वैल्यू चेन मजबूत करने, पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी और बागवानी फसलों के लिए समर्पित सहायता कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। 'भारत-VISTAAR' नामक बहुभाषी एआई टूल के जरिए किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद दी जाएगी।

शिक्षा, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा मंत्रालय को 1,39,289 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। STEM संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने, पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप, तीन नए आयुर्वेद कॉलेज और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। पर्यटन से जुड़े रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रमुख स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को प्रशिक्षित करने की योजना लाई गई है।

महिलाओं के लिए विशेष पहल

बजट में महिलाओं के लिए SHE Marts, विशेष स्किल प्रोग्राम और लखपति दीदी योजना के विस्तार का ऐलान किया गया है। हर जिले में महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव महिला शिक्षा को नई गति देगा।

एमएसएमई और उद्योग

सरकार ने 200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई को 'चैंपियन' के रूप में विकसित करने की योजना पेश की है। 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये के टॉप-अप का प्रस्ताव है। TReDS प्लेटफॉर्म को और मजबूत कर एमएसएमई को सस्ती फंडिंग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

सियासी प्रतिक्रिया

सत्ता पक्ष ने बजट को विकास और प्रगति पर केंद्रित बताते हुए इसकी आलोचना को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। विपक्ष हालांकि आम आदमी को सीधी राहत न मिलने को लेकर सवाल उठा सकता है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 तात्कालिक राहत से ज्यादा दीर्घकालिक दृष्टि वाला दस्तावेज बनकर सामने आया है। इसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है, भले ही इसके लिए अभी कुछ कठिन फैसले क्यों न लेने पड़ें।

कर व्यवस्था और निवेश

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ाई गई है। गलत जानकारी देने पर 100 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शेयर बाजार में बायबैक टैक्स, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग पर STT बढ़ाने से निवेश महंगा होगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में आयात शुल्क घटने से दवाएं और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे।

कर्ज और राजकोषीय अनुशासन

सरकार ने 2030-31 तक कर्ज-GDP अनुपात 50 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। 2026-27 में यह 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत तक लाने की योजना से साफ है कि सरकार उधार पर निर्भरता कम करना चाहती है।

राज्यों को क्या मिला

वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी निकायों के साथ आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा जोर

इस बजट में बुनियादी ढांचे को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। कुल बजट का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। सड़क, रेल, शहरी परिवहन, बंदरगाह और हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है। रेलवे के लिए करीब 2.93 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय रखा गया है, जिससे नई लाइनें, दोहरीकरण और सात नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का रास्ता खुलेगा। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार बढ़ेगा और निजी क्षेत्र का भरोसा मजबूत होगा।

एमएसएमई और उद्योगों को बढ़ावा

छोटे उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को रोजगार और निर्यात का मजबूत इंजन मानते हुए सरकार ने कई योजनाएं पेश की हैं। 200 विरासती औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन, 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत निधि में अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव इसी दिशा में कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे उद्यम तकनीक, वित्त और बाजार तक आसान पहुंच के साथ तेजी से आगे बढ़ें।

राजकोषीय अनुशासन और कर्ज नियंत्रण

इस बजट की एक बड़ी खासियत वित्तीय अनुशासन है। सरकार ने 2026-27 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। कर्ज-जीडीपी अनुपात को भी धीरे-धीरे कम करने की योजना है, ताकि ब्याज भुगतान का बोझ घटे और विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च हो सके। बजट 2026-27 साफ तौर पर राहत से ज्यादा दिशा देने वाला बजट है। इसमें आम आदमी को तात्कालिक फायदे कम जरूर दिखते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, शिक्षा और वित्तीय स्थिरता पर जो जोर दिया गया है, वह आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने की कोशिश है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बजट चुनावी नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का बजट है।

संपादकीय

निष्पादन की कसौटी पर भविष्य का भारत: अगले दशक की असली चुनौती

पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक यात्रा को अक्सर सकल घरेलू उत्पाद की तेज़ रफ्तार से मापा गया है, लेकिन यह दृष्टि इस परिवर्तन की गहराई को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती। आंकड़ों से आगे जाकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत का बदलाव केवल वृद्धि की गति का नहीं, बल्कि विकास के चरित्र और दिशा का है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जो कभी अस्थिरता, सीमित राज्य क्षमता और कमजोर बुनियादी ढांचे से जूझती थी, अब धीरे-धीरे पूंजीगत निवेश, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और संस्थागत मजबूती पर आधारित व्यवस्था में ढल रही है। यही संरचनात्मक बदलाव आने वाले दशक की बुनियाद है, और यही यह भी तय करेगा कि भारत अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल पाएगा या नहीं।

राज्य की भूमिका में आया परिवर्तन इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बीते वर्षों में सरकार ने केवल कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण पर भी गंभीर ध्यान दिया है। डिजिटल पहचान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, तेज़ भुगतान प्रणालियां, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और भौतिक बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने राज्य की क्षमता को नए स्तर पर पहुंचाया है। इसका असर यह हुआ है कि योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत कम रिसाव के साथ नागरिकों तक पहुंचने लगा है। अब चुनौती यह है कि इस मजबूत आधार को दीर्घकालिक उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापक समावेशन में बदला जाए। श्रम बाजार में औपचारीकरण इस परिवर्तन का एक अहम संकेतक है। डिजिटलीकरण और कर सुधारों ने व्यवसायों को औपचारिक दायरे में आने के लिए प्रेरित किया है, जिसका प्रमाण हाल के वर्षों में हर महीने औसतन लाखों नए कर्मियों का औपचारिक रूप से जुड़ना है। बेरोजगारी दर का पांच प्रतिशत के आसपास स्थिर रहना यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में एक स्तर की स्थिरता और लचीलापन मौजूद है। हालांकि, यह मान लेना कि औपचारिक रोजगार ही अंतिम लक्ष्य है, एक अधूरी समझ होगी। असली सवाल रोजगार की गुणवत्ता, उत्पादकता और वेतन वृद्धि का है, जो अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसके भीतर छिपी वास्तविकता अधिक जटिल है। बड़ी संख्या में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, कम उत्पादक या अवैतनिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। यह स्थिति सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत तो दर्शाती है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण की मंजिल अभी दूर है। यदि महिला श्रम शक्ति को अर्थव्यवस्था के अधिक उत्पादक क्षेत्रों से जोड़ा जाए, तो यह न केवल आय में वृद्धि करेगा, बल्कि घरेलू खपत, मानव विकास और सामाजिक स्थिरता पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा। इसके लिए कौशल प्रमाणन, अप्रेंटिसशिप और उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की कहानी उम्मीद और सीमाओं, दोनों का मिश्रण है। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि सही नीतिगत समर्थन और निरंतर निष्पादन के साथ भारत जटिल औद्योगिक क्षेत्रों में भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है। मोबाइल फोन उत्पादन और निर्यात में आया उछाल केवल एक क्षेत्रीय सफलता नहीं, बल्कि उस सोच का खंडन है कि भारत औद्योगिक नीति लागू करने में अक्षम है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और नीतिगत स्थिरता ने इस क्षेत्र को गति दी है, और इसके सकारात्मक प्रभाव रोजगार, निर्यात और तकनीकी क्षमता में साफ दिखाई देते हैं।

फिर भी, यह सफलता अपने साथ एक चेतावनी भी लाती है। विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा अभी भी सीमित है और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पूंजी-प्रधान क्षेत्रों के भरोसे व्यापक रोजगार सृजन संभव नहीं है। भारत की जनसांख्यिकीय वास्तविकता श्रम-प्रधान उद्योगों में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने की मांग करती है। टेक्सटाइल, फुटवियर, खिलौना और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति न होना यह दर्शाता है कि नीतिगत समर्थन का प्रसार अभी असंतुलित है। यदि इन क्षेत्रों में भी वही गंभीरता, लॉजिस्टिक्स सुधार और अनुपालन सरलीकरण लागू किया जाए, तो रोजगार सृजन की तस्वीर कहीं अधिक व्यापक हो सकती है।

श्रमिक-किसान कल्याण हो जीडीपी का पैमाना

> जीडीपी वृद्धि की प्रत्येक इकाई अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट का कारण भी बन रही है। इसलिए, भारत उस शहरी-औद्योगीकरण विकास मॉडल का पालन जारी रखना गवारा नहीं कर सकता, जिसने वैश्विक पर्यावरण और असमानता संकट पैदा किए हैं।

भारत के नीति-निर्माता दुविधा में हैं। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में जरूरत से बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, जिसको इसमें कार्यरत लोगों की संख्या के हिसाब से मापा जाता है, वह बहुत कम है। उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण इलाकों एवं खेतों से और लघु, 'अनौपचारिक' कारखानों और सेवा उद्यमों से भी निकालकर शहरों में लाया जाए ताकि उन्हें बड़े, 'औपचारिक' कारखानों एवं सेवा उद्यमों में काम पर लगाया जा सके।

समस्या यह है कि बड़े औपचारिक उद्यम पर्याप्त सुरक्षित नौकरियां और अच्छा वेतन नहीं दे रहे हैं। वे ज़्यादा लोगों को काम पर रखने, उन्हें अधिक तनख्वाह और सामाजिक सुरक्षा देने को तैयार नहीं हैं। इसकी बजाय, वे वेतन की लागत कम रखने के लिए अधिक 'लचीले' श्रम कानूनों की मांग कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या यह है कि सभी क्षेत्रों मसलन, विनिर्माण, सेवाएं और कृषि में नियोक्ता अपना उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंसानों के बजाय ज़्यादा मशीनरी और ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस मुख्य सुधार की ज़रूरत है, वह है व्यावसायिक उद्यम के ढर्रे और प्रचालन में सुधार। मज़दूर, चाहे वे खेतों में हों या कारखानों में, वे जिस उद्यमों में काम करते हैं उनके मालिकों की सोच होती है, उनके काम से हुआ मुनाफ़ा, उनका ही रहे और उनकी संपत्ति में इजाफा करे, न कि यह लाभ किसी वित्तीय निवेशक की संपत्ति बढ़ाने के काम आए। उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक पूंजीगत संपत्ति जैसे कि विनिर्माण उद्यम में मशीनें और खेती के लिए ज़मीन, उद्यम में काम करने वाले मज़दूरों की होनी चाहिए। मज़दूर अपने मालिक खुद हों और उन्हें स्टॉक मार्केट निवेशकों और सामंती ज़मींदारों की मल्कियत वाले कारखानों और खेतों में कर्मचारी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अपने काम से होने वाले मुनाफ़े का इस्तेमाल वह कैसे करेंगे, यह चुनने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। अब चाहे तो अपने उद्यम में और अधिक निवेश करें या अपने परिवार के कल्याण और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं। जैसा कि माइक बर्ड ने अपनी किताब 'द लैंड ट्रैप : ए न्यू हिस्ट्री ऑफ़ द वल्ड्र्स ओल्डेस्ट एसेट' नामक पुस्तक में बताया है कि भू-स्वामित्व में सुधार, जिसके तहत ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर उनके खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को हस्तांतरित की गईं, उसकी बदौलत पिछले 50 सालों में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में छोटे किसानों की आय भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। बर्ड व्याख्या करते हैं कि भारत की तुलना में अन्य देशों में सुधार तेज़ी से क्यों हुए। सभी देशों में निहित स्वार्थ सुधारों के रास्ते में आड़े आते हैं। हालांकि, उन देशों के नेताओं ने किसान-मज़दूरों के अधिकारों का समर्थन किया, न कि पूंजीपति-मालिकों का। सुधारों से छोटे किसानों की कमाई और संपत्ति बढ़ी, और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में ज़्यादा निवेश किया। गौरतलब है कि लोगों को खेती से हटाए बिना भी, कृषि-उत्पादन और कृषि उत्पादकता बढ़ी है।

अर्थशास्त्रियों और व्यापार करने वालों को उद्यमों में 'पैमाने' पर फिर से सोचना चाहिए। एक मानकीकृत वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन, चाहे यह फैक्टरी उत्पादन बढ़ाने में सहायक कोई प्रक्रिया हो या बड़े खेत में एक ही फसल उगाना, बड़ी मशीनों का उपयोग और दोहराव वाले कामों को करने के लिए कम कुशल श्रमिकों को रोज़गार देकर अपनी आर्थिक दक्षता बढ़ाता है। बड़े पैमाने के उद्यमी मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूंजी लगाने की हैसियत रखते हैं। इस तरह, उन्हें कम श्रमिक और बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करके जहां उनकी दक्षता और उत्पादन मात्रा बढ़ सकती है, और उत्पादकता भी। ऐसे उद्यम कम श्रमिकों को नौकरी पर रखते हैं। वे अर्थव्यवस्था के 'रोजगार रहित' सकल घरेलू उत्पाद बढ़ोतरी से योगदान करते हैं।

छोटे खेत जो जैविक तरीके से उन्नत किस्म की फसलें उगाते हैं, उन खेतों में उत्पादन की 'संभावना' ज़्यादा होती है। कचरा खेत में अपने आप उपयोगी अवयव बन जाता है, खासकर उन खेतों में जहां पर जानवर भी रखे होते हैं। ज़्यादा संभावना वाले खेत स्वाभाविक रूप से अधिक टिकाऊ होते हैं। ऐसे छोटे खेतों में, जिनका पैमाना कम किंतु संभावना अधिक हो, सामग्री और ऊर्जा अपने भीतर और ऐसे छोटे खेतों के आसपास ही घूमती रहती है।

पर्यावरण वैज्ञानिक वैक्लाव स्मिल ने आधुनिक उद्योगों, खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों, और वैश्विक परिवहन प्रणालियों में हाइड्रोकार्बन ऊर्जा और अन्य गैर-नवीकरणीय अवयवों की सकल व्यवस्थात्मक ज़रूरतों की गणना की है। अपनी किताब, हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स में, वह समझाते हैं कि आधुनिक एवं सघन तकनीकी विधि से बड़े पैमाने का खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली मिट्टी, पानी और वातावरण का सबसे बड़ा प्रदूषक है। वह यह भी समझाते हैं कि ज़्यादा संभावना वाले छोटे पैमाने के खेत पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक उपाय हैं। वह बताते हैं कि समस्या यह है कि इस किस्म के समाधान में ज़्यादा लोगों को ग्रामीण इलाकों में बने रहने और काम करने, और छोटे कृषि, विनिर्माण और सेवा उद्यमों में शामिल होने की ज़रूरत होगी। इसके लिए चक्र उल्टा घुमाकर लोगों को शहरी, औपचारिक उद्यमों से निकालकर ग्रामीण, अनौपचारिक उद्यमों की ओर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। विकसित देशों के नागरिक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को अन्य देशों जितनी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पहले से ही सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में है और काम करती हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की उच्चतर बढ़ोतरी से भारत के एक अरब से अधिक नागरिकों की भलाई-स्तर में सुधार नहीं होगा। पिछले 25 सालों से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अन्य बड़े देशों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की प्रत्येक इकाई में वृद्धि होने के बावजूद कम रोज़गार पैदा किया है। हमारे पास दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है, जो अच्छी कमाई वाले रोजगार की तलाश में हैं।

विकास के मौजूदा ढर्रे के साथ, पर्याप्त रोज़गार पैदा करने के वास्ते अगले कुछ सालों तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 12 प्रतिशत सालाना होनी चाहिए। जीडीपी वृद्धि की प्रत्येक इकाई अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट का कारण भी बन रही है। इसलिए, भारत उस शहरी-औद्योगीकरण विकास मॉडल का पालन जारी रखना गवारा नहीं कर सकता, जिसने वैश्विक पर्यावरण और असमानता संकट पैदा किए हैं।

हमारे देश को रहने लायक और टिकाऊ 'विकसित भारत' बनने के लिए विकास का नमूना बदलना होगा। जीडीपी पायदान पर अन्य देशों से ऊपर रहने का लक्ष्य रखने की बजाय, भारत के आर्थिक सुधारकों को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ही सुधार करना चाहिए।

हमें अपना रास्ता खोजना होगा; एक अधिक समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रास्ता; अपने देश को बनाने और अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का एक अधिक 'पारिवारिक' एवं 'सामुदायिक' तरीका —एक ज़्यादा 'गांधीवादी तरीका'— वह जो देश निर्माण करे और सभी नागरिकों को पूर्ण स्वराज (संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आज़ादी) दे सके।

प्रेरणा

जब शांति, विश्वास और संकल्प ने असंभव को झुका दिया

जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मनुष्य की परीक्षा केवल उसकी बुद्धि या कौशल से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, आत्मसंयम और विश्वास से होती है। ऐसे ही क्षण इतिहास में अमिट छाप छोड़ते हैं। डॉ. बेंजामिन कार्सन की कहानी भी उसी श्रेणी में आती है, जहां एक व्यक्ति ने न केवल चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि शांत मन और स्थिर संकल्प के साथ किया गया प्रयास असंभव को भी संभव बना सकता है। यह कहानी केवल एक जटिल ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि मानव धैर्य और नेतृत्व की उस शक्ति की है, जो संकट के समय रास्ता दिखाती है।

डॉ. बेंजामिन कार्सन एक कुशल न्यूरोसर्जन थे, लेकिन जिस चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ा, वह उनके पूरे करियर की सबसे कठिन परीक्षा थी। उनके सामने दो ऐसे जुड़वां बच्चे थे, जिनके मस्तिष्क खोपड़ी के ऊपरी हिस्से से आपस में जुड़े हुए थे। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ और जोखिम भरी थी। दोनों बच्चों की जीवन रेखाएं एक-दूसरे से इस तरह जुड़ी थीं कि थोड़ी-सी भी गलती उनके जीवन को समाप्त कर सकती थी। चिकित्सा विज्ञान के लिए यह केवल एक केस नहीं, बल्कि एक बड़ी दुविधा थी—क्या जोखिम उठाया जाए या असफलता के डर से पीछे हट जाया जाए।

ऑपरेशन से पहले पूरे अस्पताल का माहौल आशंका और तनाव से भरा हुआ था। अनुभवी डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी विशेषज्ञों के मन में कई तरह के सवाल थे। कुछ का मानना था कि दोनों बच्चों को बचा पाना लगभग असंभव है। कुछ ने यह भी कहा कि इतनी जटिल प्रक्रिया में किसी एक की जान बच जाना ही बड़ी सफलता मानी जाएगी। इन आशंकाओं के बीच डॉ. कार्सन का व्यवहार बिल्कुल अलग था। न उनके चेहरे पर घबराहट थी, न ही उनके शब्दों में संदेह। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि यदि योजना स्पष्ट हो, टीम एकजुट हो और हर कदम धैर्य से उठाया जाए, तो असंभव भी संभव हो सकता है।

डॉ. कार्सन का यह विश्वास केवल आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि वर्षों की साधना, अनुभव और अनुशासन का परिणाम था। उन्होंने ऑपरेशन से पहले हर पहलू पर गहराई से विचार किया। संभावित जोखिमों को चिन्हित किया गया, हर चरण की बार-बार समीक्षा की गई और टीम के हर सदस्य को उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाई गई। डॉ. कार्सन जानते थे कि इस तरह के लंबे और जटिल ऑपरेशन में तकनीकी कौशल जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी मानसिक संतुलन भी है। उन्होंने टीम को केवल निर्देश नहीं दिए, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराया कि वे सब मिलकर एक असाधारण कार्य करने जा रहे हैं।

जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो समय जैसे थम गया। यह प्रक्रिया केवल घंटों की नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा थी। ऑपरेशन कुल 22 घंटे तक चला। हर क्षण नया खतरा और नई चुनौती सामने आ रही थी। कभी रक्तस्राव का जोखिम बढ़ जाता, तो कभी मस्तिष्क की नाजुक संरचना निर्णय को और कठिन बना देती। ऐसे समय में घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन होती है। डॉ. कार्सन ने हर कदम बेहद संयम और सावधानी से उठाया। उन्होंने बार-बार रुककर स्थिति का आकलन किया, टीम से विचार-विमर्श किया और फिर आगे बढ़े।

इस पूरी प्रक्रिया में डॉ. कार्सन केवल एक सर्जन नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने महसूस किया कि जब टीम के किसी सदस्य पर थकान या तनाव हावी होता है, तो उसे केवल तकनीकी निर्देश नहीं, बल्कि भावनात्मक संबल की भी आवश्यकता होती है। वे लगातार टीम का मनोबल बढ़ाते रहे, उन्हें याद दिलाते रहे कि यह प्रयास केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि दो मासूम जिंदगियों के भविष्य से जुड़ा है। उनका शांत स्वभाव और स्थिर आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में एक भरोसेमंद ऊर्जा का संचार कर रही थी।

22 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद वह क्षण आया, जिसका सभी को इंतजार था। दोनों बच्चों को सुरक्षित रूप से एक-दूसरे से अलग कर लिया गया। यह केवल एक सफल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि चिकित्सा इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। जिस कार्य को असंभव माना जा रहा था, वह धैर्य, योजना और सामूहिक प्रयास से संभव हो गया। इस सफलता ने डॉ. बेंजामिन कार्सन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, लेकिन उससे भी अधिक यह सफलता मानव संकल्प की शक्ति का प्रतीक बन गई।

इस घटना की सबसे बड़ी सीख यह है कि असली सफलता जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपी होती है। डॉ. कार्सन ने यह सिद्ध किया कि संकट के समय घबराना आसान होता है, लेकिन शांत रहकर सही निर्णय लेना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने यह भी दिखाया कि जब टीम में विश्वास और एकता होती है, तो सबसे कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल प्रतिभा या ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मानसिक स्थिरता और निरंतर प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।

आज जब जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दबाव और जल्द परिणाम पाने की होड़ है, तब डॉ. बेंजामिन कार्सन की यह कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम न केवल समस्याओं का समाधान खोजते हैं, बल्कि स्वयं को भी एक बेहतर इंसान के रूप में गढ़ते हैं। यही कारण है कि यह कहानी केवल चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग दिखाने वाली प्रेरक मिसाल बन जाती है।

एक बार फिर चर्चा में आए भारतीय स्टार्टअप्स, कर्तव्य पथ पर दिखी कौशल विकास की झांकी

गणतंत्र दिवस 2026 की परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही, लेकिन कर्तव्य पथ पर सबसे अधिक ध्यान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की झांकी ने खींचा। इस झांकी ने दुनिया को दिखाया कि भारत का युवा अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता है।

झांकी में प्रदर्शित स्वदेशी हाइब्रिड यूएवी 'जोल्ट' और 'टेथर्ड' ड्रोन प्रणालियों ने न केवल देश की सैन्य शक्ति को गौरवान्वित किया, बल्कि भारतीय स्टार्टअप्स की उस अदम्य क्षमता का भी लोहा मनवाया, जो पिछले एक दशक में फली-फूली है। गणतंत्र दिवस की परेड में स्टार्टअप्स की इस भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं, बल्कि धरातल पर उतरता सच है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2026 के पहले 'मन की बात' में इन स्टार्टअप्स का विशेष जिक्र करना दर्शाता है कि आने वाला दशक 'इनोवेशन' और 'एंटरप्रेन्योरशिप' (नवाचार और उद्यमिता) का ही होगा और अब भारत एक 'फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स' (भविष्य के लिए तैयार कार्यबल) का केंद्र बनने के लिए मजबूती से तैयार है।

वर्ष 2026 'स्टार्टअप इंडिया' अभियान की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। जनवरी 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, तब लक्ष्य था भारत में नवाचार के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना। 2016 में मुट्ठी भर स्टार्टअप्स से शुरू हुआ यह सफर आज दो लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स अब केवल ई-कॉमर्स या सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, वे अब डीप-टेक और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कदम रख चुके हैं। 2024-26 के बीच इस क्षेत्र में सबसे अधिक 'सूनिकार्न' (भावी यूनिकॉर्न) देखे गए हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी में 'जोल्ट' हाइब्रिड यूएवी का प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि भारत के कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड का इन्वेंटर बना दिया है। जोल्ट जैसे ड्रोन, जो वर्टिकल टेक-ऑफ और लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम हैं, पूरी तरह से भारतीय दिमाग की उपज हैं। इसी प्रकार टेथर्ड ड्रोन प्रणालियां घंटों तक एक ही स्थान पर हवा में रहकर निरंतर डाटा प्राप्त कर सकती हैं, जो सीमाओं की निगरानी के लिए क्रांतिकारी हैं। संदेश स्पष्ट है कि भारत का स्टार्टअप मिशन अब रोजगार और अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षित युवाओं ने स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिससे पिछले दशक में 21 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। इसने नवाचार का लोकतंत्रीकरण भी किया है। अब नवाचार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा; 'जोल्ट' जैसी तकनीकों के पीछे टियर-2 और टियर-3 शहरों के प्रतिभावान इंजीनियरों का हाथ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 'मन की बात' में इस पर विशेष जोर दिया था कि स्टार्टअप अब केवल दिल्ली-बेंगलुरु जैसे महानगरों तक सीमित नहीं हैं। आज 45% से 50% स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहे हैं। छोटे शहरों के युवा अब खेती (एग्री-टेक), शिक्षा (एड-टेक) और स्वास्थ्य (हेल्थ-टेक) जैसे क्षेत्रों में तकनीक के माध्यम से स्थानीय समस्याओं के समाधान खोज रहे हैं।

भारत आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मात्र एक दशक के भीतर भारतीय युवा 'जॉब सीकर' (नौकरी मांगने वाला) से 'जॉब क्रिएटर' (नौकरी देने वाला) बनने की दिशा में इतनी लंबी छलांग लगाएगा। स्टार्टअप इंडिया ने उनमें 'फेलियर' (असफलता) के डर को खत्म कर 'रिस्क' (जोखिम) लेने के साहस को सम्मान दिया है।

स्टार्टअप इंडिया ने न केवल अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि देश में ऐसी संस्कृति पैदा की है जहां 'असफलता' को अंत नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा माना जाता है। इस अभियान की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश के लगभग हर जिले से एक स्टार्टअप निकल रहा है। यदि यह गति बनी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन लैब बनकर उभरेगा।

भारतीय स्टार्टअप्स के कुछ बेहतरीन नवाचार, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर डाला प्रभाव...

भारत आज दुनिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में पहले नंबर पर है और इसका श्रेय पेटीएम, फोन-पे और रेजर-पे जैसे स्टार्टअप्स को जाता है। इन्होंने कैशलेस इकोनॉमी को संभव बनाया। आज एक छोटे रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक, हर जगह क्यूआर कोड के जरिए भुगतान सामान्य बात है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स ने भारत का नाम रोशन किया है। स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला निजी राकेट 'विक्रम-एस' लांच कर इतिहास रचा। वहीं पिक्सेल नामक स्टार्टअप अत्याधुनिक उपग्रह बना रहा है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की उच्च-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें और डाटा प्रदान करते हैं। फिजिक्सवाला और बायजूस जैसे स्टार्टअप्स ने ऑनलाइन माध्यम से कोरोना काल में शिक्षा को सुलभ बनाया। यद्यपि बायजूस की छलांग और पतन दोनों ही अब केस स्टडी हैं, परंतु डिजिटल लर्निंग में यह ऐसा मुहावरा बन गया था, जिसने कई एजुकेशनल स्टार्टअप्स की राह प्रशस्त की। डिजिटल लर्निंग घर-घर पहुंची और अब एक छोटे गांव का छात्र भी नाममात्र की फीस पर देश के सबसे अच्छे शिक्षकों से आईआईटी-जेईई या यूपीएससी की तैयारी कर सकता है।

अभियान

शीत, कोहरा और समय को चुनौती देती आस्था: माघी पूर्णिमा पर संगम तट पर विश्वास का महासंगम

प्रयागराज की धरती पर माघी पूर्णिमा का दिन इस बार केवल एक धार्मिक तिथि भर नहीं रहा, बल्कि यह उस अडिग आस्था का प्रतीक बन गया, जिसे न कड़ाके की ठंड डिगा सकी और न ही घने कोहरे की चादर रोक पाई। रविवार को माघ मेले के दौरान संगम और गंगा तट पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ा, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की आत्मा आज भी उसी श्रद्धा, विश्वास और परंपरा से संचालित होती है, जो सदियों से इसे दिशा देती आई है। सुबह आठ बजे तक करीब 90 लाख श्रद्धालुओं द्वारा गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाना केवल एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह उस जीवंत सांस्कृतिक चेतना का प्रमाण था, जो हर पीढ़ी में नए रूप में प्रवाहित होती रहती है। शनिवार की आधी रात से ही प्रयागराज की सड़कों, गलियों और मेला क्षेत्र में हलचल शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवा शरीर को कंपकंपा रही थी, तापमान लगातार नीचे बना हुआ था और कोहरे की मोटी परत दृश्यता को सीमित कर रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुके। दूर-दराज के गांवों, कस्बों और शहरों से आए लोग अपने परिवारों के साथ संगम की ओर बढ़ते रहे। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी, तो कोई गंगा जल के पात्र को संभाले हुए था। चेहरे पर ठंड की लकीरें जरूर थीं, लेकिन आंखों में श्रद्धा की चमक साफ दिखाई दे रही थी। माघी पूर्णिमा का स्नान माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व माना जाता है। विशेष रूप से उन कल्पवासियों के लिए, जिन्होंने पूरे एक महीने तक संगम तट पर कठिन नियमों, संयम और साधना के साथ जीवन बिताया, यह दिन उनकी तपस्या की पूर्णाहुति जैसा होता है। प्रशासन के अनुसार, इस वर्ष लगभग पांच लाख कल्पवासी मेला क्षेत्र में कल्पवास कर रहे थे। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ उनका कल्पवास पूर्ण हुआ, इसलिए बड़ी संख्या में उनके परिजन भी प्रयागराज पहुंचे। यह दृश्य अत्यंत भावुक था, जब एक महीने तक तप और त्याग में लीन रहे कल्पवासी अंतिम स्नान के बाद संगम तट को नमन करते और अपने अनुभवों को आंखों में समेटे घर लौटने की तैयारी करते दिखाई दिए। रविवार की सुबह घना कोहरा पूरे मेला क्षेत्र पर छाया हुआ था। दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी सभी घाटों पर स्नान की प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित रूप से चलती रही। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कहीं कोई धक्का-मुक्की नहीं, न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था। हर डुबकी के साथ गूंजते 'हर हर गंगे' और 'हर हर महादेव' के जयघोष वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ठंड और कोहरा भी इस आस्था के आगे नतमस्तक हो गए हों। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन तैयारियां भी उसी स्तर की थीं। सभी प्रमुख और सहायक घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें हर समय सतर्क रहीं। गंगा की धारा पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। नाविकों और प्रशिक्षित गोताखोरों को घाटों पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। कड़ाके की ठंड और ठंडे जल के बावजूद किसी बड़ी अप्रिय घटना का न होना प्रशासनिक सतर्कता और बेहतर समन्वय का प्रमाण रहा।

मेला क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग भी इस आयोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहा। जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे मेला क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहे और हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए रखी। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, बल्कि श्रद्धालुओं के मन में भी विश्वास बना रहा कि वे सुरक्षित वातावरण में अपनी आस्था का निर्वहन कर रहे हैं। लाखों लोगों की मौजूदगी के बावजूद स्नान व्यवस्था का सुचारू रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

माघ मेला केवल स्नान का आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है। संगम तट पर साधु-संतों की छावनियां, अखाड़ों की गतिविधियां, यज्ञ-हवन, प्रवचन और भजन-कीर्तन का सिलसिला पूरे मेले को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। माघी पूर्णिमा के दिन यह वातावरण और भी अधिक गहन हो गया। स्नान के बाद श्रद्धालु दान-पुण्य में जुट गए। अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता को इस दिन विशेष पुण्य माना जाता है, और लोगों ने खुले मन से इसमें भाग लिया। यह दृश्य बताता है कि आस्था केवल व्यक्तिगत मोक्ष की कामना नहीं, बल्कि सामाजिक करुणा और सहभागिता से भी जुड़ी हुई है।

कल्पवासियों के लिए माघी पूर्णिमा का दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण का अनुभव होता है। एक महीने तक सादगी, नियम और संयम के साथ बिताया गया समय उन्हें भीतर से बदल देता है। कई कल्पवासी स्नान के बाद भावुक हो उठे। उनके लिए यह समय आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और जीवन की भागदौड़ से विराम लेने का अवसर होता है। कल्पवास के दौरान बनी मित्रताएं, साझा कठिनाइयां और आध्यात्मिक साधना की स्मृतियां उनके साथ जीवन भर के लिए चली जाती हैं।

प्रयागराज का माघ मेला यह भी दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिकता किस तरह एक साथ चल सकती हैं। एक ओर हजारों वर्षों पुरानी धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक प्रशासन, तकनीक और प्रबंधन उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित रूप देने में जुटे हैं। यह संतुलन ही इस आयोजन को अद्वितीय बनाता है। इतनी विशाल संख्या में लोगों का एकत्र होना और फिर भी व्यवस्था का नियंत्रण में रहना भारत की संगठन क्षमता का जीवंत उदाहरण है।

माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेले का एक प्रमुख चरण पूर्ण हो गया है, लेकिन आस्था की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ माघ मेला अपने समापन की ओर बढ़ेगा। तब तक संगम तट पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का यह प्रवाह निरंतर बना रहेगा। हर दिन यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल गंगा में डुबकी लगाते हैं, बल्कि अपने साथ मानसिक शांति, आशा और आत्मिक ऊर्जा भी लेकर लौटते हैं।

कुल मिलाकर, माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में उमड़ा यह जनसागर केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह दृश्य बताता है कि चाहे मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, आस्था की ऊष्मा उसे परास्त कर सकती है। गंगा में लगाई गई हर डुबकी केवल जल से स्पर्श नहीं, बल्कि उस परंपरा से जुड़ाव है, जिसने सदियों से लोगों को एक सूत्र में बांधे रखा है। यही कारण है कि कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकी और संगम तट पर विश्वास की यह अनवरत धारा एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो गई।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

केंद्रीय बजट 2026-27

यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने वाला बजट है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2026-27 का बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने वाला बजट है।

केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार हुआ बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। इन तीन कर्तव्यों में पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और इसे बनाए रखना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता निर्माण करना है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ, सबका विकास के विजन के अनुरूप है और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित सभी के विकास को प्राथमिकता देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में 'ग्यान' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ ही दिव्यांगजनों का आधार मजबूत होगा। इतना ही नहीं, समाज के सभी क्षेत्रों और प्रत्येक वर्ग को विकसित भारत के निर्माण में शामिल करने का बहुत ही सराहनीय दृष्टिकोण रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस केंद्रीय बजट से गुजरात को भविष्य में होने वाले फायदों का स्वागत करते हुए कहा कि लोथल और धोलावीरा का देश के पुरातात्विक विरासत क्लस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट में समावेश हुआ है। इससे गुजरात में पर्यटन के माध्यम से 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार होगा। देश में 20 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के लिए 10 हजार टूरिस्ट गाइड तैयार करने की योजना से गुजरात के आइकॉनिक टूरिस्ट स्थलों में भी स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने इसे शहरी विकास को नई दिशा देने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में शहरी उत्कर्ष के लिए प्रधानमंत्री की अटूट संकल्पबद्धता प्रतिबिंबित हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-टू और टियर-श्री शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की घोषणा से राज्य के छोटे शहरों का सुव्यवस्थित विकास में तेजी आएगी।

देश में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के मामले में गुजरात के अग्रणी होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार का प्रशंसनीय

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- कर्तव्य भवन में तैयार हुआ बजट तीन कर्तव्यों से प्रेरित है
- समाज के सभी क्षेत्रों और प्रत्येक वर्ग को 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र से कवर करने का सराहनीय दृष्टिकोण
- लोथल और धोलावीरा का पुरातात्विक विरासत क्लस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट में समावेश होने से पर्यटन के माध्यम से गुजरात में 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार होगा
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-टू और टियर-श्री शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की घोषणा से राज्य के छोटे शहरों के सुव्यवस्थित विकास में तेजी आएगी
- एमएसएमई से लेकर बड़े उद्योग, यह सभी के लिए प्रोत्साहक बजट है
- टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 6 योजनाओं का लाभ गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा

कदम है। इस बजट में म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए जिन प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है, उसका लाभ गुजरात की म्युनिसिपालिटीज को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से लेकर बड़े उद्योगों, सभी के लिए प्रोत्साहक बजट है। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, साथ ही एमएसएमई पर भी बल दिया गया है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बड़ा फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योगों के लिए घोषित किए गए प्रोत्साहन भी गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करेंगे तथा टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 6 योजनाओं का लाभ भी राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, तीन केमिकल पार्क की घोषणा तथा बायोफार्मा इंडस्ट्रीज के लिए की गई 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा का भी लाभ गुजरात के इन क्षेत्रों के उद्योगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा देश की क्रिटिकल मिनरल की जरूरत में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम साबित होगी।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में मुख्य औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, शोध संस्थानों, कौशल केंद्रों और रिहायशी परिसरों वाले इस सुनियोजित शैक्षणिक जोन से राज्यों के स्किल इकोसिस्टम को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए सूरत को पूर्वी भारत के दानकुनी के साथ जोड़ने की घोषणा लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की दिशा में एक 'मास्टर स्ट्रोक' साबित होगी। दक्षिण गुजरात के उद्योग जगत के पास अब पूर्वी भारत की ओर व्यापार करने के लिए 'हाई-स्पीड' कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो राज्य के व्यापार और अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देगी। इसके अलावा, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा से देश में जल मार्ग के क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में खादी, हथकरघा और हस्तकला को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से संपर्क स्थापित करने और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रोसेस और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इतना ही नहीं, बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा करदाताओं का सम्मान किया है और उन्हें देश के विकास की प्रेरक शक्ति बताया है। इस बजट में भी करदाताओं के सम्मान का ख्याल रखते हुए ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में टैक्स जमा करने में हुई गलती को अपराध नहीं, बल्कि भूल मानते हुए सजा के बदले जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यह भी प्रशंसनीय है।

मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय और जनसामान्य सहित सभी के सर्वग्राही विकास, कल्याण तथा विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उनके योगदान को और अधिक प्रेरणा देने वाले बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

बजट के बाद बाजार में हड़कंप, टैक्स फैसलों से निवेशकों का भरोसा डगमगाया

जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय बजट के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार में जो तस्वीर उभरी, उसने यह साफ कर दिया कि इस बार निवेशकों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं। बजट से पहले बाजार में यह धारणा बनी हुई थी कि सरकार पूंजी बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत दे सकती है, खासकर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगाए जाने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कटौती की लंबे समय से मांग चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसटीटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, बाजार की दिशा अचानक बदल गई और निवेशकों की भावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ गया।

बजट में फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी की दर 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत और ऑप्शन ट्रेडिंग पर 0.10 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव सामने आते ही बाजार में बेचैनी फैल गई। डेरिवेटिव सेगमेंट में बड़ी संख्या में सक्रिय निवेशकों और ट्रेडरों को यह फैसला सीधा झटका लगा। उनका मानना है कि इससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी, छोटे निवेशकों के लिए बाजार में बने रहना मुश्किल होगा और कुल मिलाकर बाजार की तरलता पर असर पड़ेगा। यही कारण रहा कि बजट भाषण के दौरान और उसके तुरंत बाद बाजार में तेज बिकवाली शुरू हो गई।

इस नकारात्मक माहौल का असर प्रमुख सूचकांकों पर बेहद साफ दिखा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। एक समय ऐसा आया जब सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर गिरावट में चले गए, जो बाजार में फैली व्यापक कमजोरी को दर्शाता है। दिन के अंत में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद 26 शेयर लाल निशान में बंद हुए और केवल चार शेयर ही बढ़त के साथ टिक पाए। निफ्टी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही और इसके 50 में से 43 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

इंट्रा-डे कारोबार में बाजार की घबराहट अपने चरम पर दिखाई दी। सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से 2,873.23 अंक तक फिसल गया, जबकि निफ्टी में 869.15 अंकों की तेज गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने निवेशकों के मनोबल को भी झटका दिया। छोटे निवेशक, जो बजट के बाद स्थिरता की उम्मीद कर रहे थे, अचानक बढ़े टैक्स बोझ और बाजार की गिरावट से सतर्क हो गए। वहीं, संस्थागत निवेशकों ने भी जोखिम कम करने की रणनीति अपनाते हुए बिकवाली का रास्ता चुना।

सेक्टोरल स्तर पर देखें तो आईटी सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टरों में दबाव बना रहा। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब चार प्रतिशत तक टूट गया, जिससे सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। मेटल इंडेक्स में लगभग 3.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भी दो से तीन प्रतिशत तक की कमजोरी नजर आई। यह साफ संकेत था कि बाजार ने बजट के कर प्रस्तावों को व्यापक रूप से नकारात्मक माना है।

हालांकि इस भारी उथल-पुथल के बीच आईटी सेक्टर एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जिसने बाजार को कुछ राहत दी। शेयर बायबैक के टैक्सेशन में किए गए बदलावों से आईटी कंपनियों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे आईटी इंडेक्स दिन के निचले स्तर से लगभग चार प्रतिशत तक उछल गया। विप्रो और टीसीएस जैसे दिग्गज शेयरों में दो प्रतिशत से अधिक की मजबूती दर्ज की गई और आईटी इंडेक्स के 10 में से आठ शेयर हरे निशान में बंद हुए। इससे यह संकेत मिला कि निवेशक अभी भी उन सेक्टरों में भरोसा जता रहे हैं, जहां टैक्स बदलाव अपेक्षाकृत अनुकूल नजर आए।

कुल मिलाकर बजट के बाद शेयर बाजार की प्रतिक्रिया यह बताती है कि निवेशक टैक्स नीति से संतुष्ट नहीं हैं। जहां सरकार विकास, राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर जोर दे रही है, वहीं पूंजी बाजार के लिए बढ़ता टैक्स बोझ निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है। बाजार सहभागियों का मानना है कि अगर ट्रेडिंग लागत इसी तरह बढ़ती रही, तो इससे निवेश का माहौल कमजोर पड़ सकता है। अब निवेशकों की नजर सरकार और नियामकों की आगे की रणनीति पर टिकी है कि क्या आने वाले समय में बाजार की भावनाओं को संभालने के लिए कोई सकारात्मक संकेत दिए जाएंगे या नहीं। फिलहाल, बजट के बाद बाजार में जो अस्थिरता और असंतोष दिखा है, वह यह साफ करता है कि निवेशकों को राहत नहीं, बल्कि एक बड़ा झटका महसूस हुआ है और भरोसा बहाल होने में वक्त लग सकता है।

कमर्शियल गैस महंगी, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत बरकरार

जीएनएस)। नई दिल्ली। फरवरी की शुरुआत के साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिली-जुली खबर सामने आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर महंगाई का दबाव बढ़ा है, लेकिन आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी ताजा दरों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1,740.50 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1,691.50 रुपये का था। इसी तरह कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 1,844.50 रुपये हो गई है, जबकि जनवरी में यह 1,795 रुपये में उपलब्ध था। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1,692 रुपये तक पहुंच गए हैं और चेन्नई में इसकी कीमत 1,899.50 रुपये तय की गई है। अलग-अलग शहरों में दरों में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर उन व्यवसायों को प्रभावित करेगी, जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए बड़े पैमाने पर गैस का उपयोग करते हैं।

दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में यह सिलेंडर 853 रुपये में ही उपलब्ध रहेगा, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये बनी हुई है। लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी और पटना जैसे अन्य शहरों में भी घरेलू गैस के दाम जस के तस हैं। उल्लेखनीय है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार बदलाव 8 अप्रैल 2025 को किया गया था, इसके बाद से अब तक इसमें स्थिरता बनी हुई है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के दामों के साथ-साथ टैक्स संरचना पर निर्भर करती हैं। जनवरी महीने में वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसका असर फरवरी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में दिखाई दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को लागत की समीक्षा करती हैं और उसी आधार पर नए रेट घोषित किए जाते हैं, इसलिए कमर्शियल गैस के दामों में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान बढ़ी हुई लागत को किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहने से आम लोगों के मासिक बजट को फिलहाल राहत मिली है। कुल मिलाकर, फरवरी की शुरुआत में गैस की कीमतों में यह बदलाव एक बार फिर दिखाता है कि जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल का सीधा असर कमर्शियल सेक्टर पर पड़ता है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार और कंपनियों की नीति के तहत फिलहाल स्थिरता का लाभ मिल रहा है।

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने चर्चगेट पर मीडिया को संबोधित किया

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 1 फरवरी 2026 को चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर चल रहे जन-जागरूकता अभियान "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा जिम्मेदार रेल यात्रा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार ने आम जनता से वैध टिकट खरीदकर जिम्मेदारीपूर्वक यात्रा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खरीदा गया टिकट सीधे तौर पर रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास, यात्री सुविधाओं के उन्नयन तथा सुरक्षा

प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में योगदान देता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि टिकट से प्राप्त राजस्व रेलवे के सुचारु संचालन, क्षमता विस्तार एवं सेवा सुधार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आगे विस्तार से बताते हुए महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि नैतिक टिकटिंग एवं स्वैच्छिक अनुपालन रेलवे की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने जोर दिया कि यात्रियों का जिम्मेदार व्यवहार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण प्रयासों को सशक्त बनाता है और विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है।

पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के साथ निरंतर संवाद, जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा सभी यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा कर इस अभियान को सफल बनाने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। सामूहिक जिम्मेदारी, अनुशासन और सहयोग के माध्यम से पश्चिम रेलवे यात्री विश्वास, परिचालन दक्षता और सेवा उत्कृष्टता को और सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है, जिससे विकसित भारत के व्यापक उद्देश्य में योगदान दिया जा सके।

फियो ने केंद्रीय बजट 2026–27 की सराहना की; एक मज़बूत निर्यात-सक्षम, उद्योग-अनुकूल और एमएसएमई -केंद्रित बजट के लिए सरकार को धन्यवाद: फियो अध्यक्ष, श्री एस

जीएनएस)। नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) केंद्रीय बजट 2026–27 का गर्मजोशी से स्वागत करता है और सरकार को एक साहसिक, दूरदर्शी और सुधार-उन्मुख बजट पेश करने के लिए बधाई देता है जो भारत की विकास यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से मज़बूत करता है, साथ ही भारतीय निर्यात, विनिर्माण और एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को निर्णायक रूप से बढ़ाता है।

बजट पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने माननीय वित्त मंत्री और सरकार के प्रति निरंतर आर्थिक विकास, राजकोषीय विवेक, बुनियादी ढांचे के विस्तार और विश्वास-आधारित शासन के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उपाय व्यापार और निवेश इकोसिस्टम को और अधिक ऊर्जा देंगे और निर्यातकों को एक स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल प्रदान करेंगे।श्री रल्हन ने कहा, "केंद्रीय बजट 2026–27 स्पष्ट रूप से भारत की आर्थिक क्षमता को ठोस प्रदर्शन में बदलने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। विनिर्माण, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर मज़बूत ज़ोर—सार्थक कर और सीमा शुल्क सुधारों द्वारा समर्थित—भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक गहराई से और प्रतिस्पर्धी रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा।"

फियो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कपड़ा, रसायन, विमान घटक, निर्माण उपकरण और दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट जैसे उच्च-मूल्य और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करने के लिए सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करता है। 200 पुराने औद्योगिक समूहों के प्रस्तावित पुनरुद्धार, कई क्षेत्र-विशिष्ट पहलों के साथ, पैमाने, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात की तैयारी में सुधार की उम्मीद है। श्री रल्हन ने कहा कि उद्योग भारत के निर्यात पदचिह्न का विस्तार करने के लिए इन पहलों का सक्रिय रूप से लाभ उठाने के लिए तैयार है। व्यापार सुविधा उपायों का स्वागत करते हुए, श्री रल्हन ने कहा कि प्रमुख इनपुट पर शुल्क छूट, निर्यात समय-सीमा का विस्तार, विश्वसनीय निर्यातकों की पहचान और कारखाने परिसर से

निर्यात कार्गो की निकासी से लेनदेन लागत में काफी कमी आएगी, व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा और आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "ये सुधार सीधे तौर पर निर्यातक के आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेंगे।"

फियो अध्यक्ष ने एमएसएमई के लिए सरकार के मज़बूत और सोचे-समझे सपोर्ट की भी तारीफ़ की, जिसमें तीन तरह के तरीके अपनाए गए हैं: 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड को बढ़ाना, टीआरईडी पर सीपीसीई की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग, और इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। श्री रल्हन ने कहा, "एमएसएमई भारत के निर्यात इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। बजट में तरलता सहायता, इक्विटी समावेश और प्रोफेशनल कैपेसिटी-बिल्डिंग पर फोकस एमएसएमई को आगे बढ़ने, इनोवेशन करने और ग्लोबल चैंपियन बनने के लिए सशक्त करेगा।"

फियो ने सर्विस सेक्टर पर नए सिरे से ज़ोर देने का भी स्वागत किया—जिसमें आईटी, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, शिक्षा, डिज़ाइन, खेल और केयर इकोनॉमी शामिल हैं—जिसे सेफ हार्बर प्रावधानों और ज़्यादा टैक्स निश्चितता से सपोर्ट मिला है। ये उपाय, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, जलमार्गों और ऊर्जा सुरक्षा पर लगातार सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के साथ मिलकर, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगे और एक वैश्विक सेवाओं और विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत करेंगे।

पश्चिम रेलवे – रतलाम

शुद्धिपत्र

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे, निम्नलिखित कार्य हेतु **IREPS** पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं। **निविदा क्रमांक** : EL/TRD/58/2x25/EPC-PSI/01. **दिनांक** : 29/01/2026, **कार्य का नाम** : पश्चिम रेलवे के रतलाम डिविजन के गोधरा–रतलाम खंड के बीच 2x25केवी फीडिंग सिस्टम के लिए 132/55केवी स्कॉट कनेक्टेड ट्रेक्शन सबस्टेशन और स्विचिंग पोस्ट का डिज़ाइन, आपूर्ति, संस्थापन, जांच एवं कमीशनिंग। **अनुमानित लागत** : ₹146,06,00,000/–, **बयाना राशि** : ₹74,53,000/–, **समापन अवधि** : 24 महीने। **निविदा दस्तावेज की राशि** : शून्य, **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय** : 16/02/2026 को 15:00 बजे की जगह 02/03/2026 को 15:00 बजे तक। **तकनीकी बोलियां खोलने की दिनांक एवं समय** : 27/02/2026 को 15:30 बजे की जगह 13/03/2026 को 15:30 बजे तक। **प्रस्ताव की वैधता** : खुलने की तिथि से 180 दिन। **वेबसाईट** : www.ireps.gov.in. **नोटिस बोर्ड** : वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने।

SNP-435

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

आम बजट 2026-27: यूपी–बिहार के लिए विकास की नई रेखा, कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगी तस्वीर

जीएनएस)। लखनऊ/पटना/वाराणसी। केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में किए गए बड़े प्रावधानों से दोनों राज्यों की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में जहां उत्तर प्रदेश को हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क और शहरी विकास के बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, वहीं बिहार को जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की सौगात दी गई है। राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि पूर्वी भारत के उत्थान की स्पष्ट रूपरेखा है।

उत्तर प्रदेश के लिए बजट में विकास का पिटारा खोल दिया गया है। वाराणसी को दो बड़े हाई-स्पीड ग्रीन रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच बनेगा, जिससे राजधानी और पूर्वांचल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित है, जो पूर्वी भारत को सीधे जोड़ने का काम करेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को लगभग 1,500 किलोमीटर लंबाई के हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।

काशी के लिए एक और बड़ी घोषणा गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और कार्गो वेसल्स की मरम्मत के लिए आधुनिक सेंटर की स्थापना को लेकर की गई है। इससे जलमार्ग आधारित परिवहन को मजबूती मिलेगी और वाराणसी एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरेगा। इसके साथ ही समुद्री विमान संचालन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना और राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार की घोषणा से प्रदेश की नदियों पर आधारित अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। यूपी में पहले से ही पांच नदियों पर जलमार्ग से जुड़े काम चल रहे हैं, जिन्हें अब और गति मिलने की उम्मीद है।

शहरी विकास के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए देशभर में 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यूपी के ऐसे 25 शहर—जिनमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, नोएडा, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, अलीगढ़,

मुरादाबाद और उन्नाव जैसे प्रमुख नगर शामिल हैं—इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। बेहतर सड़कें, परिवहन, जलापूर्ति, सीवरेज और स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाओं से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट ने मजबूत संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है, जिससे दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के मामलों में समय पर इलाज संभव होगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए नए गर्ल्स हॉस्टल, कौशल विकास के लिए आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी स्टेम संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को मंजूरी मिलना उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित यह पार्क न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा छोटे तीर्थ स्थलों के विकास की योजना के तहत सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भी नई पहचान मिलेगी।

हैंडलूम और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की शुरुआत से उत्तर प्रदेश की एक जिला, एक उत्पाद योजना को नई ताकत मिलेगी। इससे कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ेगी और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को समेटने वाला दस्तावेज है, जो विकसित भारत की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। बिहार के लिए भी आम बजट 2026-27 उम्मीदों से भरा हुआ है। राज्य को जलमार्ग, हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य माल ढुलाई की लागत को कम करना और बिहार को पूर्वी भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाना है। गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन नदियों के जल नेटवर्क को मजबूत करने की योजना से राज्य में आंतरिक जल परिवहन को नई दिशा मिलेगी। पटना में जहाजों और कार्गो वेसल्स की मरम्मत और तकनीकी सेवाओं के लिए उच्चस्तरीय सेंटर की स्थापना से उद्योग और व्यापार को बड़ा सहारा मिलेगा। बजट में बिहार के सामाजिक ढांचे पर भी खास ध्यान दिया गया है। प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शहरी विकास से जुड़े प्रावधानों से राज्य के शहरों को आधुनिक स्वरूप देने में मदद मिलेगी। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस से बिहार को औद्योगिक निवेश, आधारभूत ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को देश के दीर्घकालीन विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा से देश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी। विशेष रूप से वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जबकि पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना से राज्य के उद्योग, व्यापार और निर्यात गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

कुल मिलाकर आम बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विकास की नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और जलमार्ग जैसे क्षेत्रों में किए गए बड़े निवेश से न केवल आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले वर्षों में यूपी और बिहार देश के विकास इंजन के रूप में उभर सकते हैं।

नेपाली और भारतीय जाली मुद्रा का बड़ा जाल बेनकाब, सीमा पार तक फैला था नेटवर्क

जीएनएस)। पूर्वी चंपारण। भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सक्रिय जाली मुद्रा के एक बड़े और संगठित रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई को सीमा सुरक्षा और आर्थिक अपराधों के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने तीन नेपाली नागरिकों और सात भारतीयों समेत कुल दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में नेपाली और भारतीय जाली मुद्रा के साथ-साथ नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला पूरा प्रिंटिंग सेटअप भी बरामद किया गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और सीमा क्षेत्र में नकली नोटों की सुनियोजित सप्लाई कर रहा था।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में तिलक बहादुर थिंग, सरोज कुमार, दिलीप कुमार सिंह, श्रीदेव महतो, रौशन कुमार, राकेश सिंह, साहेब कुमार उर्फ लाल, साजन कुमार, विकास कुमार पटेल और मोहम्मद असलम शामिल हैं। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केवल गिरफ्तारी तक सीमित कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए जांच को हर पहलू से आगे बढ़ाया जाएगा।

इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 25 लाख रुपये की नेपाली जाली मुद्रा और लगभग 18 हजार रुपये की भारतीय फेक करेंसी बरामद की है। इसके अलावा विशेष कागज, आधुनिक प्रिंटिंग मशीन, स्याही, कटर और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। बरामद सामग्री को देखकर यह स्पष्ट है कि जाली नोट बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किए जा रहे थे, ताकि आम लोगों

और व्यापारियों को आसानी से धोखे में रखा जा सके।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार को इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में जाली नोटों की बड़ी खेप की आवाजाही की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। रक्सौल एसडीपीओ मनीष आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने सीमा क्षेत्र में सघन जांच अभियान शुरू किया।

जांच के दौरान बाइक से आ रहे दो नेपाली नागरिकों को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 18 हजार रुपये की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि जाली नोटों की छपाई बिहार के सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज इलाके में की जा रही है। इस अहम जानकारी के आधार पर मोतिहारी और सीतामढ़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने मेजरगंज में छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस को एक ठिकाने से बड़ी मात्रा में नेपाली जाली नोट मिले और वहां जाली नोट छापने का पूरा सेटअप बरामद हुआ। इससे यह साफ हो गया कि यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था, जो नेपाल और भारत दोनों देशों की मुद्रा को निशाना बनाकर सीमा क्षेत्र में खपाने का काम कर रहा था। एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि अब तक तीन नेपाली और सात भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी से गहन पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अब यह जानने में जुटी है कि यह नेटवर्क कब से सक्रिय था, जाली नोट किन-किन इलाकों में सप्लाई किए गए और क्या इसके तार अन्य राज्यों या अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से भी जुड़े हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस रैकेट के पीछे बड़े आर्थिक अपराधियों का हाथ हो सकता है, जिन तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा।

इस कार्रवाई को इंडो-नेपाल सीमा पर जाली मुद्रा के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सीमा क्षेत्र में निगरानी और सख्त की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के आर्थिक अपराधों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

पहाड़ों में बर्फ और बारिश का कहर कड़ाके की ठंड से ठिठुरा उत्तराखंड

जीएनएस)। उत्तरकाशी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है और कड़ाके की ठंड ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू होने से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत कई ऊपरी क्षेत्रों में रविवार से लगातार हिमपात हो रहा है, जिससे पर्वत चोटियां बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गई हैं। सुबह से लेकर रात तक गिरती बर्फ और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ों में शीतलहर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में अगले तीन दिनों तक मौसम खराब बना रह सकता है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के साथ-साथ निचले और मैदानी इलाकों में भी बारिश, तेज हवाएं और आंधी-तूफान का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते प्रदेश के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड के तेवर और तीखे हो सकते हैं।

रविवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही प्रदेश के कई जिलों में मौसम तेजी से बिगड़ा है। चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी हिमपात का अनुमान है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और दिन में भी सर्द हवाओं से लोग ठिठुरने को मजबूर हैं।

मौसम विभाग ने कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ तूफान आने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों पर जमी बर्फ के कारण फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। कई स्थानों पर यातायात धीमा पड़ गया है और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है।

उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और आसपास के सभी तहसील क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, सुखी टॉप, राड़ी टॉप और आसपास के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद परत नजर आ रही है, जिससे पूरा इलाका शीतल और शांत दिखाई दे रहा है। हालांकि यह नजारा देखने में बेहद आकर्षक है, लेकिन ठंड और नमी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया है।

मौसम के इस बदले मिजाज ने किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। ओलावृष्टि और अत्यधिक ठंड से रबी की फसलों और सेब सहित अन्य फलों की बागवानी को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शीतकालीन तीर्थयात्रा पर निकले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवाओं और खराब दृश्यता के कारण कई स्थानों पर आवाजाही जोखिम भरी हो गई है।

प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव के इंतजाम करने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अगले कुछ दिनों तक मौसम अपडेट पर नजर रखें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा से बचें और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। लगातार बदलते मौसम के बीच पहाड़ों में एक बार फिर सर्दी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और जनजीवन को धीमा कर दिया है।

“मेरा टिकट, मेरी शान - विकसित भारत के लिए मेरा योगदान” अभियान के अंतर्गत जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा डिजिटल रेलवे सेवाओं के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरूण जैन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से चलाए जा रहे “मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान” अभियान के अंतर्गत 01 फरवरी, 2026 (रविवार) को जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जूनागढ़ के माननीय विधायक श्री संजयभाई कोराडीया, महापौर श्री धर्मेश पॉशिया, उप-महापौर श्री आकाश कटारा, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री पुनीत शर्मा, भाजपा उपाध्यक्ष गीताबेन, भाजपा दंडक श्री कल्पेश अजवानी, बक्शी पंच

प्रदेश मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री जे. के. चावड़ा सहित अन्य स्थानीय गणमान्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विद्यालयी विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों एवं विद्यार्थियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व से अवगत कराया और यह संदेश दिया कि टिकट लेकर यात्रा करना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से आम जनता और विद्यार्थियों में जिम्मेदार यात्रा की भावना को सुदृढ़ किया गया।

वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को रेलवन (RailOne) ऐप की विस्तृत जानकारी दी गई। ऐप के प्रमुख लाभों—जैसे आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी तथा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं—के बारे में विस्तार से बताया गया और डिजिटल सेवाओं को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल रेलवे सेवाओं को अपनाने तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विद्यालयी बच्चों ने जागरूकता नारे लगाकर यात्रियों से “टिकट लेकर ही यात्रा करें” की अपील की। इस अभियान से जहाँ यात्रियों में रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी, वहीं विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों, ईमानदार यात्रा और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई।

यह जन-जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव सिद्ध हुआ, जिससे उनमें आत्मविश्वास के साथ-साथ समाज के प्रति सकारात्मक भागीदारी की भावना का विकास हुआ। पश्चिम रेलवे द्वारा बच्चों को इस अभियान का हिस्सा बनाकर भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण की दिशा में एक सार्थक पहल की गई।

खेलों को मिली नई उड़ान, बजट 2026-27 में खिलाड़ियों और खेल उद्योग पर खुलकर खर्च

जीएनएस)। नई दिल्ली। आम बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि खेल अब सिर्फ मनोरंजन या पदक तक सीमित विषय नहीं रहा, बल्कि यह देश के सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक भविष्य का अहम हिस्सा बन चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। कुल 4479.88 करोड़ रुपये के इस बजट ने न केवल खिलाड़ियों में उत्साह भरा है, बल्कि खेल से जुड़े उद्योग, प्रशिक्षकों, स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर पर काम कर रहे संगठनों को भी नई ऊर्जा दी है। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 3346.54 करोड़ रुपये से 1133 करोड़ रुपये अधिक है, जो सरकार की बदली हुई प्राथमिकताओं को साफ तौर पर दर्शाती है।

इस बजट की सबसे अहम और ऐतिहासिक घोषणा खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को लेकर की गई है। पहली बार इस क्षेत्र के लिए सीधे 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अब तक खेल बजट का अधिकांश हिस्सा प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और प्रशासनिक खर्चों में जाता रहा, लेकिन इस बार सरकार ने खेल उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले खेल उपकरण और सामग्री निर्माण को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत के पास उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती खेल सामग्री का वैश्विक केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। इस पहल से खेल उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे ‘मेक इन इंडिया’ के तहत घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं और स्टार्टअप्स को नया बाजार मिलने की संभावना है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

खिलाड़ियों की तैयारी और प्रशिक्षण के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़ा भरोसा दिखाया है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साइ के बजट में बढ़ोतरी कर इसे 880 करोड़ रुपये से 917.38 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साइ देशभर में राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन,

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने और स्टेडियमों के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाता है। बजट बढ़ने से उम्मीद की जा रही है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक उपकरण और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी। हालांकि, इसी बजट में डोपिंग से जुड़े संस्थानों के आवंटन में कटौती की गई है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी के बजट में कमी को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की साख बनाए रखने के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है।

सरकार के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया को भी इस बजट में अहम स्थान मिला है। इसके लिए 924.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। भले ही यह राशि पिछले वर्ष की घोषित रकम से थोड़ी कम हो, लेकिन सरकार का जोर अब खेलो इंडिया को एक व्यापक मिशन के रूप में आगे बढ़ाने पर है। वित्त मंत्री ने ‘खेलो इंडिया मिशन’ की घोषणा करते हुए कहा कि अगले दशक में प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ के व्यवस्थित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह मिशन जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक प्रतिभा विकास की एकीकृत प्रणाली तैयार करेगा, जिसमें खेल विज्ञान, तकनीक, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और प्रतियोगिताओं की अहम भूमिका होगी। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि में भी बड़ा इजाफा किया गया है। इसे 28.05 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग 78 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वर्ष जुलाई-अगस्त में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए यह फैसला भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी 28 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे पदक विजेताओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को और बेहतर समर्थन मिल सके।

बजट में खेल से जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता राशि में बढ़ोतरी, युवा हॉस्टलों के बजट में कई गुना इजाफा और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अधिक आवंटन यह संकेत देते हैं कि सरकार खेल और युवा विकास को एक साथ जोड़कर देख रही है। हालांकि, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के बजट में कटौती भी देखने को मिली है, जिस पर आने वाले दिनों में बहस होने की संभावना है।

कुल मिलाकर बजट 2026-27 खेलों के लिए सिर्फ खर्च बढ़ाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें खेल को स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और वैश्विक पहचान से जोड़ा गया है। बढ़ा हुआ बजट, खेल सामग्री उद्योग को मिला नया प्रोत्साहन और खेलो इंडिया मिशन जैसे फैसले आने वाले वर्षों में भारत को खेल के मैदान के साथ-साथ खेल उद्योग में भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।